भारत - कोरिया गणराज्य संबंध

भारत - कोरिया गणराज्य (आर ओ के) संबंधों ने हाल ही के वर्षों में बहुत गति पकड़ी है और ये वास्तव में बहु-आयामी हो गए हैं, जो हितों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान से प्रोत्साहित हुए हैं। द्विपक्षीय कोंसुलर संबंध 1962 में स्थापित हुए थे जिनको 1973 में राजदूत के स्तर पर स्तरोन्नत किया गया। कालांतर में, कोरिया गणराज्य की मुक्त बाजार नीतियां भारत के आर्थिक उदारीकरण एवं 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप बनी। दोनों कोरियाओं के शांतिपूर्ण पुन: एकीकरण के लिए भारत के सतत समर्थन का इस देश में अच्छा स्वागत किया गया।

13वीं सदी में लिखित "समगुकयूसा" अथवा "दी हैरिटेज हिस्ट्री ऑफ दी थ्री किंगडम्स" के अनुसार, वर्ष 48 ईस्वी में अयोध्या से एक राजकुमारी (सूरिरत्ना) कोरिया आई, राजा किम-सूरो से विवाह किया और रानी हूर ह्वांग-ओक बनी [अन्य के साथ-साथ, पूर्व राष्ट्रपति ली म्युंग-बक की पत्नी (श्रीमती किम यून-ओक), पूर्व राष्ट्रपति किम दाये-जुंग, पूर्व राष्ट्रपति किम युंग-सैम और पूर्व प्रधान मंत्री किम जोंग-पिल उसी शाही युगल की संतति हैं]। कोरिया के बौद्ध भिक्षु हायचो (704-787 सी ई) या होंग जियाव ने ईस्वी सन् 723 से 729 तक भारत का भ्रमण किया तथा "भारत के पांच रजवाड़ों की तीर्थयात्रा" नामक यात्रा वृतांत लिखी जिसमें भारत की संस्कृति, राजनीति एवं समाज का स्पष्ट विवरण है। यह यात्रा वृत्तांत कई वर्ष तक खोया रहा और फिर इसे 1908 में चीन में पॉल पेलियॉट द्वारा पुन: खोजा गया और बाद में उसे यूनेस्को के तत्वावधान में हिंदी सहित अलग - अलग भाषाओं में अनूदित किया गया। मूल प्रति इस समय फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी के स्वामित्व में है। नोबल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर ने कोरिया के शानदार अतीत और उज्ज्वल भविष्य के बारे में वर्ष 1929 में एक विचारोत्तेजक कविता - 'लैम्प ऑफ दी ईस्ट' की रचना की थी।

राजनीतिक संबंध

वर्ष 1945 में कोरिया की आजादी के बाद भारत ने कोरिया के मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई थी। भारत के श्री के पी एस मेनन कोरिया में चुनाव करवाने के लिए 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे। कोरिया युद्ध (1950-53) के दौरान, युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया, और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल ए जी रंगराज के नेतृत्व में 60वें भारतीय पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट (मेडिकल मिशन) ने कोरिया संघर्ष के दौरान अपनी साख बनाई। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के. एस. थिमैया ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यर्पण आयोग (एनएनआरसी) के अध्यक्ष के रूप में काम किया और युद्ध विराम के बाद, युद्ध से उठे मुद्दों का मानवीय आधार पर समाधान करने में योगदान किया, जिसे सभी

ओर से प्रशंसा मिली। भारतीय सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम करार की 60वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 26 से 27 जुलाई 2013 तक कोरिया गणराज्य का दौरा किया।

फरवरी 2006 में राष्ट्रपति डॉ0 ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा की गई कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों के एक नए दैदीप्यमान दौर की शुरुआत की। इससे अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर निर्णय लेने के लिए एक कार्य बल के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 01 जनवरी, 2010 को इस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावी किया गया। राष्ट्रपति ली ने 26 जनवरी 2010 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में महत्वपूर्ण दौरा किया, तब द्विपक्षीय संबंध कूटनीतिक भागीदारी के स्तर पर जा पहुँचे थे। इसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 24 से 27 जुलाई 2011 तक कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा की थी, और उस दौरान सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 24 से 27 मार्च 2012 तक द्विपक्षीय और परमाणु सुरक्षा दोनों के संबंध में शिखर वार्ताओं के लिए सिओल की राजकीय यात्रा की थी, जिसके दौरान वीजा सरलता करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15 से 18 जनवरी 2014 तक राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाये की भारत की राजकीय यात्रा के साथ, परंपरागत घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध गुणवत्तापूर्ण उच्चतर स्तर के संबंध बन गए।

विदेश मंत्री ने 28 से 30 दिसंबर 2014 तक दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्रा की और अपने काउंटरपार्ट विदेश मंत्री युन ब्युंग-से के साथ भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत के विदेश मंत्री तथा कोरिया के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में विकास की व्यापक रूप से समीक्षा की तथा विदेश मंत्री ने मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनने के लिए कोरिया को न्यौता दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 और 19 मई 2015 को कोरिया का राजकीय दौरा किया जो उनकी सरकार के पहले वर्ष के अंदर हुआ। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध को 'विशेष सामरिक साझेदारी' के रूप में स्तरोन्नत किया गया। 'विशेष सामरिक साझेदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य' में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पार्क गुएन ही विदेश कार्यालय के सचिव / उप मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर दो प्लस दो परामर्श तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोरियाई कंपनियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए एक "कोरिया प्लस" समूह का गठन करने का प्रस्ताव किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) श्री शिवशंकर मेनन ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 30 जून से 2 जुलाई 2013 तक सिओल की यात्रा की। एक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कोरिया गणराज्य की यह पहली यात्रा थी। कोरिया के उप राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकार किम क्यू ह्यू ने मार्च 2015 में भारत का दौरा किया तथा हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ चर्चा की।

पूर्ववर्ती रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी ने सितंबर 2010 में कोरिया गणराज्य का दौरा किया। कोरिया के रक्षा मंत्री श्री किम क्वान जिन ने 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2012 के दौरान भारत का दौरा किया। रक्षा सचिव, वरिष्ठ भारतीय सैन्य एवं सिविल अधिकारियों तथा एक भारतीय रक्षा उद्योग शिष्टमंडल के साथ रक्षा मंत्री श्री मनोहर पार्रिकर ने 16 अप्रैल 2015 से कोरिया गणराज्य की तीन दिवसीय यात्रा की और अपने कोरियाई समकक्ष जनरल हान मिन कू के साथ भारत - कोरिया गणराज्य रक्षा मंत्री बैठक की सह अध्यक्षता की।

पिछले साल की अन्य उच्च स्तरीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं : मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विश्व शिक्षा मंच 2015 के लिए 18 से 22 मई के दौरान कोरिया का दौरा किया, रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने यूरेशिया परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर असेम गोष्ठी के लिए 9 से 12 सितंबर, 2015 के दौरान कोरिया का दौरा किया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. हर्षवर्धन ने भारत - कोरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए कोरिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान अगले 3 सालों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा, पंजाब के उप मुख्य मंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रमश: सितंबर और अक्टूबर 2015 में कोरिया का दौरा किया।

कोरिया गणराज्य की ओर से एक आधिकारिक एवं कारोबारी शिष्टमंडल के साथ बुसान के मेयर श्री सूह बुयांग सू एवं उनकी पत्नी ने मंत्रालय के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के तहत 12 से 15 मार्च, 2015 के दौरान दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरू का दौरा किया। कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर श्री चुंग यूई ह्वा ने 8 से 10 मई, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। स्पीकर श्री चुंग ने लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। सरकारी कानून मंत्री श्री जे जियांग बू ने 9 से 11 सितंबर 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। एक कारोबारी शिष्टमंडल के साथ पोहांग के मेयर श्री ली कांग डियोक ने डी वी पी के तहत दिल्ली, आगरा और मुंबई का दौरा किया तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लिया।

वाणिज्यिक संबंध

व्यापार एवं आर्थिक संबंधों ने फिर से गति पकड़ना शुरू कर दिया है। 2014 में द्विपक्षीय व्यापार 18.07 बिलियन डालर पर पहुंच गया। भारत कोरिया का 15वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। प्रधानमंत्री की यात्रा ने भारत पर एक सकारात्मक फोकस का मार्ग

प्रशस्त किया जिसने पोत निर्माण, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण एवं विनिर्माण विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। अलग से नई दिल्ली में अक्टूबर 2015 में भारत - आर ओ के द्विपक्षीय हवाई सेवा करार को संशोधित किया गया जिससे हवाई संपर्कों की संख्या बढ़कर प्रति सप्ताह 19 हो गई। भारत के साथ व्यापार करने की इच्छुक कोरियाई कंपनियों की मदद के लिए जनवरी 2010 में कोरिया में एक भारतीय वाणिज्य चैंबर स्थापित किया गया।

कोरिया के अग्रणी मीडिया ग्रुप "चोसुन ग्रुप" और सी आई आई ने नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2016 के दौरान भारत - कोरिया व्यवसाय शिखर बैठक का आयोजन किया। कोरिया प्रायद्वीप के शीर्ष नेतृत्व तथा नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर, व्यापार, उद्योग एवं ऊर्जा उप मंत्री ने इस शिखर बैठक में भाग लिया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक अनन्य गोलमेज बैठक भी शामिल थी।

कोरिया की सैमसंग, ह्युंदई मोटर्स और एलजी जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में 3 बिलियन डालर से अधिक के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। कोरिया गणराज्य में भारतीय निवेश पहले ही दो बिलियन डॉलर को पार कर चुके हैं। आधिकारिक रूप से कोरिया की छोटी-बड़ी 603 फर्में हैं जिन्होंने भारत में कार्यालय खोल रखे हैं। हिंडाल्को की एक सहयोगी कंपनी, नोवेलिस ने 600 मिलियन डॉलर का निवेश करके कोरिया की एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है (अब कोरिया गणराज्य में उनका कुल निवेश लगभग 2 बिलियन डॉलर हो गया है)। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने कोरिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी सांगयोंग मोटर्स का एक बड़ा हिस्सा मार्च 2011 में लगभग 360 मिलियन डॉलर का निवेश करके अधिग्रहीत कर लिया है। टाटा मोटर्स ने मार्च 2004 में दाइवू वाणिज्यिक वाहन कंपनी को 102 मिलियन डॉलर में अधिग्रहीत कर लिया है। कोरिया में मौजूद अन्य भारतीय कंपनियों में आईटी मेजर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि हैं।

सांस्कृतिक संबंध :

भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बुसान में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (आई सी सी) का गठन किया गया। आई सी सी आर के अध्यक्ष डा. कर्ण सिंह द्वारा यात्रा के साथ जून 2011 से मार्च 2012 तक कोरिया में पहले भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। लोक सभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार ने मई 2011 में सिओल में रबीन्द्रनाथा टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। आई सी सी आर द्वारा उपहार में प्रदान की गई महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण 21 जुलाई 2014 को बुसान में होंगबियोप-सा मंदिर में किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारतीय योग एवं कत्थक-सह-समसामयिक नृत्य निर्देशकों की प्रतिनियुक्ति की है जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर नियमित

रूप से कक्षाएं आयोजित करते है। स्थानीय लोगों में भारतीय संस्कृति में लगातार बढ़ती रुचि के चलते स्थानीय शिक्षकों के साथ हिंदी, तबला और कुकिंग कक्षाएं भी आरंभ की गई हैं। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आवधिक आधार पर व्याख्यान, प्रदर्शनी एवं परफार्मेंस का आयोजन किया जाता है। सारंग जो कोरिया में भारत का अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव है, के पहले चरण का आयोजन सियोल, बुसान और चुनचियान में 9 से 15 नवंबर 2015 के दौरान किया गया।

एफ एस आई और कोरिया राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (के एन डी ए) ने मार्च 2012 में एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) क्रमश: कोरिया अध्ययन एवं कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय ने भी कोरियाई लोगों की अच्छी-खासी मौजूदगी से और तमिलनाडु के ह्युंदई मोटर्स से प्रोत्साहित हो कर एक कोरियन अध्ययन विभाग खोला है। हाल ही में झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरियन भाषा में पांच वर्षीय समेकित स्नातकोत्तर डिग्रियां आरंभ की हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज कोरियन भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

जेएनयू ने कोरिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों, जिनमें योनसेई विश्वविद्यालय, कोरिया विश्वविद्यालय, हैनकुक विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय और पुसान विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय शामिल हैं, के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी कोरिया विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। दो कोरियाई विश्वविद्यालयों, नामत: सिओल के हैनकुक विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय और बुसान विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय, में भारतीय अध्ययन विभाग हैं। वर्ष 2012 में सिओल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने एशियाई भाषा और सभ्यता का नया विभाग स्थापित किया था जिसमें वे भारतीय अध्ययनों में बड़े पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। कोरिया के विभिन्न अन्य विश्वविद्यालय भारतीय दर्शन, योग और आयुर्वेद में डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

सिओल फोरम फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद संयुक्त रूप से भारत-कोरिया संवाद आयोजित करते रहे हैं जो दोनों देशों की सरकारों की द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए नीतियों और व्यावहारिक उपायों के संबंध में सिफारिशें करता है। नवंबर 2014 में सियोल में 13वीं बैठक और नवंबर 2015 में दिल्ली में 14वीं बैठक का आयोजन किया गया।

3 दिसंबर 2013 को कोरिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ (कीटा) में भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया (आईआईएसके) की स्थापना की गई थी। डॉ. ली ओ-सून की अध्यक्षता में, भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया (आईआईएसके) एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरियाई शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। 'इंडिया फॉर्च्यून'

सांसदों, वरिष्ठ कोरियाई अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए 'भारत प्रगत प्रबंधन कार्यक्रम' का आयोजन करता रहा है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, कॉरपोरेट माहौल और भारतीय संस्कृति शामिल है। भागीदारों को हमेशा परिचय यात्रा के लिए भारत दौरे पर लाया जाता है। यह एक कोरियाई विद्वान डॉ0 ओह ह्वासिओक की पहल का एक निजी व्यावसायिक प्रमोशन है।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहा है।

भारत सरकार भारत में अध्ययन के लिए हर साल अनुसंधान कार्य एवं अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों एवं विषय क्षेत्रों के लिए कोरिया के नागरिकों के लिए छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों की पेशकश करती है। आयुष छात्रवृत्ति योजना में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा और होम्योपैथी में पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाती है जबकि केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा हिंदी भाषा छात्रवृत्ति की पेशकश की जा रही है। कोरिया गणराज्य सरकार भी चुनिंदा कोरियाई विश्वविद्यालयों में मास्टर और पीएच.डी स्तर पर कोरियाई भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

भारतीय समुदाय

अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 11000 के आसपास है। पी आई ओ की संख्या 120 के आसपास है। 1000 भारतीय अध्येता कोरिया में मुख्यत: विज्ञान के स्नातकोततर एवं पीएचडी. पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुख्य रूप से आई टी, जहाजरानी एवं आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अनेक पेशेवरों ने कोरिया गणराज्य में पलायन किया है। उनमें से अधिकांश सैमसंग, एल जी, ह्युंदई, टाटा दायवू तथा टी सी एस के साथ काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षाविदों की संख्या भी उल्लेखनीय है।

भारतीयों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मिशन ने समन्वय समिति के अंग के रूप में कोरिया गणराज्य में विभिन्न भारतीय संघों को एक साझे प्लेटफार्म पर लाया है। समिति सूचना के प्रसार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के समन्वय के लिए एक कारगर प्लेटफार्म के रूप में साबित हुई है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, सिओल की वेबसाइट:

http://www.indembassy.or.kr/

*****

फरवरी 2016